Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

भारत में राजनीतिक पर्यावरण और स्थाई विकास

डॉ. अजय कुमार
एसोसिएट प्रोफ़ेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, गुरुनानक खालसा कॉलेज, करनाल।

पर्यावरण अर्थात हमारे चारों तरफ मौजूद वस्तुएँ, परिस्थितियाएँ, प्रभावकारी तत्व जिन्होंने हमें धेरा हुआ है जो प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती हैं पर्यावरण का रूप हैं। मनुष्य को अगर आत्मा और शरीर दो भागों में बांटा जाए तो उसके लिए पर्यावरण के भी दो रूप होंगे। एक तो जिसने उसकी आत्मा को घेरा है और दूसरा वो जिसने उसके शरीर को घेरा है। हालांकि आत्मा के बारे में कुछ लोगों का विचार है कि ये होती ही नहीं जबकि कुछ इसे शरीर से भी महत्त्वपूर्ण और अजर, अमर मानते हैं। मेरे विचार में आत्मा होती है लेकिन ये किसी व्यक्ति का वो हिस्सा है जो भौतिक रूप में दिखाई नहीं देता बल्कि वैचारिक रूप में महसूस किया जाता है और जैसे वैचारिक माहौल में मनुष्य रहता है वैसा ही उसकी आत्मा के लिए पर्यावरण तैयार हो जाता है। कैसे विचारों का पर्यावरण आत्मा को दूषित करेगा, पतित करेगा या उज्जवलित करेगा ये उस पर्यावरण में उपस्थित तत्त्वों की विशेशता पर निर्भर करेगा। मनुष्य का दूसरा भाग जो भारीर है अपना भौतिक स्वरूप रखता है और भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। भौतिक अर्थात जिसे हम अपनी इन्द्रियों के माध्यम से महसूस करते हैं। भौतिक जगत में होने वाली घटनाओं के कारण प्रभाव को तथ्यपर ढंग से स्पष्ट प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी कारण जब पर्यावरण से जुड़े किसी विषय पर बात होती है तो इसका मतलब लगभग–2 भौतिक पर्यावरण से ही समझा जाता है। लेकिन जैसा कि इस प्रस्ताव का विशय 'राजनीतिक पर्यावरण' से सम्बन्धित है इसलिए यहाँ भौतिक और वैचारिक दोनों प्रकार के पर्यावरण से जुड़े तथ्यों पर प्रकाश डालना जरूरी है।

जैसा कि विषय है 'भारत में राजनीतिक पर्यावरण और स्थाई विकास' तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत क्या है? संविधान के अनुसार भारत जो कि इंडिया भी कहलाता है एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें रहने वाले सभी नागरिक समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार रखते हैं। ये एक प्रभुत्व सम्पन्न देश है इसलिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि में शामिल होना या न होना, ये अपने विवेक से तय करेगा। दूसरा ये जानना जरूरी है कि 'राजनीति' यानि राजव्यवस्था को बनाए रखने की नीति। राजव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रभुसत्ताधारी तय करेगा कि मूल्यपरम तत्त्वों का बँटवारा किस ढंग से किया जाए। प्रभुसत्ताधारी बनने अर्थात राजव्यवस्था को अपने हाथ में लेने और उसे बनाए रखने के लिए राजनीति का प्रयोग होता है और राजनीतिक पर्यावरण में वो सब कुछ आ जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष राजनीति से जुड़ा है। जहाँ तक स्थाई विकास का प्रश्न है तो एक ऐसा विकास जो आज भी लाभकारी है और कल व लगातार आने वाले कलों के लिए लाभकारी होगा। हमें जिसका फायदा हो रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को जिसका फायदा लगातार होता रहेगा।

अब मूल विषय का विश्लेषण करते है कि भारत में राजनीतिक पर्यावरण की वर्तमान स्थिति क्या है। जैसा कि भारत एक समाजवादी देश है लेकिन क्या वर्तमान में भारत में वास्तव में समाजवादी मूल्यों की रक्षा हो रही है। अगर तथ्यों पर प्रकाश डाले तो 1991 के

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

बाद से वैश्विक स्तर पर समाजवादी भाक्तियाँ कमजोर हुई हैं लेकिन भारत मे ंतो बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन देखने को मिले हैं। भारत में पंडित जवाहर लाल नेहरू, इन्दिरा गाँधी और राजीव गाँधी के बाद पूँजीवाद अत्यन्त शक्तिशाली बनकर उभरा है। देश की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियाँ विचारधारा के तौर पर लगभग एक जैसी नज़र आती हैं। वामपंथी पार्टियाँ लगातार कमजोर हो रही हैं। निजीकरण का प्रभाव और परिस्थितियाँ हर तरफ दिखाई देने लगी हैं। सरकारी क्षेत्र लगातार घाटे में जाते दिखाई देने लगे हैं और ठीक–ठाक चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों का भी निजी क्षेत्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है। विदेशी कम्पनियाँ अपना प्रभाव इतना बढ़ा चुकी हैं कि सरकारी नीतियों को अपने अनुसार आसानी से लागू करा सकती हैं। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा लगभग पतन की तरफ जा रही है योजना आयोग, जो कि भारत में व्यवस्थित विकास के लिए बनाई गई एक महत्त्वपूर्ण संस्था, जो समाप्त कर दी गई है। जैसा कि देखा जा रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र से भी सरकारी सहायता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, निजी शिक्षण संस्थान लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन उनके द्वारा जन सेवा के स्थान पर लगातार मुनाफा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार की नीतियों के कारण सरकारी उपक्रमों की दशा खराब हो रही है भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) इसका उदाहरण है जहाँ मुनाफे की काफी संभावनाओं के बावजूद निजी क्षेत्र की तुलना में वो लगातार पिछड़ रहा है।

इंडियन एयरलाइंस जिससे सरकार काफी मुनाफा और जनहित प्राप्त कर सकती है उसे भी निजी भागेदारी के लिए तैयार कर दिया है। सरकार द्वारा निजी संस्थानों को ज्यादा सहायता, सार्वजनिक क्षेत्र को कम मदद और लगातार निजीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की समस्या खड़ी हो रही है। निजी क्षेत्र में रोजगार के नाम पर आम जन का शोषण लगातार बढ़ रहा है। बेरोजगारी की समस्या के कारण युवाओं व अन्यों में आक्रोश और अवि वास बढ़ रहा है और ये परिस्थितियाँ भारतीय राजनीतिक वातावरण और पर्यावरण को दूषित कर रही हैं। मध्य वर्ग लगातार अमीरों की तुलना में गरीबी की तरफ जा रहा है जिसके कारण समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जाने वाले मध्य वर्ग में भी सरकारी नीतियों के प्रति घृणा पैदा हो रही है और किसान लगातार पूँजीपतियों के शोषण का शिकार हो रहे हैं। किसानों को उनकी मेहनत का उचित लाभ नहीं मिल रहा और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आत्म हत्याएँ करनी पड़ रही हैं। मजदूर अपने परिवार का खर्चा उठाने में अपने आपको असमर्थ महसूस कर रहा है। छोटे व्यापारी बाजार में बड़ी कम्पनियों से टक्कर नहीं ले पा रहे और अपना काम छोड़कर नौकरियों की तलाश कर रहे हैं लेकिन वहाँ भी उनके हाथ खाली रह जाते हैं क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों का अभाव है निजी क्षेत्र में बहुत ज्यादा शोषण। आज राजनीतिक लोग भी अपनी बात को पूँजीपतियों की विचारधारा के अनुसार ही रख रहे हैं। ये सभी बातें भारतीय राजनीतिक पर्यावरण के लिए हानिकारक सि़द्ध हो रही हैं। भारत में पथनिरपेक्षता संवैधानिक रूप से प्रदान की गई है और लगातार इस सिद्धान्त का पालन करने का भी प्रयास किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भारत में लगातार धार्मिक उन्माद भी देखने को मिलता रहा है। विशेष तौर पर राजनीतिक हित के लिए धर्म को इस्तेमाल किया जाता रहा है जहाँ भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी धार्मिक तुष्टिकरण या अल्पसंख्यक व दलित ध्रुवीकरण पर विशेष नजर रखती है, वहीं दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा हिन्दूवाद और

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

दक्षिण पंथी विचार पर अधिक बल डालकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्शों की राजनीति को देखें तो स्पष्ट नजर आता है कि 1984 के सिख विरोधी वर्गों के बाद जहाँ कांग्रेस को बड़ी संख्या में वोट पड़े वहीं 2013 के यू.पी. दंगों के बाद बी.जे.पी. को अत्यंत ज्यादा फायदा हुआ। ये लगातार देखा गया है कि चुनाव के समय धार्मिक मुद्दे और दंगों की चर्चा ज्यादा बढ़ जाती है। चुनाव के समय धार्मिक नफरत से भरे संदेशों का सोशल मीडिया पर खूब प्रचार–प्रसार किया जाता है और ये सभी किसी पार्टी विशेष को तो फायदा पहुँचा देता है। हमारे संविधान में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आजादी को बनाए रखने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी धार्मिक अल्पसंख्यक अपने आपको धार्मिक अहिष्णुता का शिकार पाते हैं और बहुसंख्यकों के दबाव में उन्हें आसानी से गलत दिशा के लिए एकत्रित कर दिया जाता है और ये सब राजनीतिक व्यवस्था में भी नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ाता है।

राजनीतिक नकारात्मकता धार्मिक अहिष्णुता को रोक पाने में असमर्थ होती है और इस प्रकार राजनीतिक पर्यावरण लगातार दूषित होता जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक काम कर रही है लेकिन लोकतंत्रीय गुण व्यवस्था नाम के लिए रह गए हैं। आज विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ लोकतांत्रिक सिद्धांतों का नाम मात्र के लिए पालन करती है जबकि ज्यादातर पार्टियों में परम्परागत चले आ रहे परिवारों के व्यक्ति ही बागडौर संभालते हैं। दूसरा ये स्पष्ट देखने को मिलता है कि मिचैल्स का आयरन लॉ ऑफ ऑलिगाकी' का सिद्धांत वर्तमान भारतीय प्रजातंत्र पर स्पष्ट लागू होता है। वर्तमान में यहाँ किसी भी पार्टी के लगभग सभी नेताओं को पार्टी के प्रमुख नेताओं के अनुसार ही चलना पड़ता है। पार्टी के प्रमुख नेताओं सरकार के कुछ विशेष मंत्रियों, कुछ नौकरशाहों और कॉरपोरेट जगत के कुछ लोगों से मिलकर पूरे प्रजातंत्र को अपनी जक्कड़ में ले लिया है। जनता के अधिकार वोट डालने तक सीमित रहते नजर आ रहे हैं और वोट डालने में भी वे अपने विवेक से कहीं ज्यादा मीडिया द्वारा बनाए झूठे वातावरण के कारण प्रभावित हो रहे हैं। देश में जाति, धर्म, पैसा, डर और विभिन्न मुद्दों पर लोगों का मस्तिष्क इस तरीके से घुमाया जाता है कि वे वास्तविकता को जानने की बजाए भावना के आधार पर वोट डालते हैं। इस प्रकार प्रजातंत्र में जनता का अपने शासक को चुनने का अधिकार उसके पास रहते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से उससे दूर कर दिया है।

भारत में सभी लोगों को न्याय और अधिकार देना संवैधानिक रूप से जरूरी है। सैद्धान्तिक रूप से सभी लोग भारत में समान रूप से सभी अधिकार रखते भी हैं लेकिन व्यावहारिक रूप से अगर देखें तो आज भी भारत में सामाजिक रूप से जातिगत भेदभाव राजनीति में जातिवाद और आरक्षण राजनीति के अहम मुद्दे बने हुए हैं। आज देश में जाति के नाम पर झगड़े और नफरत देखने को मिलती है। देश की आजादी के इतने वर्शों बाद भी कई क्षेत्रों में जातिगत छूआछुत देखने को मिलता है। कई बार अखबारों में पढ़ते हैं कि किसी गांव में किसी चलित जाति के युवक को शादी में घोड़ी से नीचे उतार दिया या दलित युवक की बारात नहीं चढ़ने दी। कई बार उच्च जाति व भिन्न जाति के बीच तनाव या निम्न जाति के लोगों को गांव से पलायन जैसी घटनाओं के बारे में और कई बार निम्न जाति की बस्ती को जलाने जैसी घटनाएँ सुनने को मिलती हैं। कई बार राजनीति में जातिगत आरक्षण

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

का मुद्दा भयकर रूप में सामने आता है। आप जानते हैं कि आरक्षण अछूत, निम्न और कमजोर लोगों के लिए दिया गया लेकिन अब ये एक परम्परा बन चुका है किसी भी जाति के लोग न सिर्फ आरक्षण की माँग करते हैं बल्कि किसी जाति से नेता के रूप में उभरने का भी ये एक अलग तरीका बन चुका है लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता कि इस प्रकार की राजनीति से सम्पूर्ण समाज और राष्ट्र को कितना नुकसान होता है। यहाँ तक कि वो जाति ही अगर आरक्षण नहीं ले पाती तो सबसे ज्यादा नुक्सान में भी रहती है क्योंकि एक तो उसे आरक्षण के संघर्ष में अपने लोगों का समय, पैसा और कई बार जीवन तक बर्बाद करना पड़ता है, दूसरे उस जाति की छवि दूसरी जातियों की नजर में नकरात्मक बन जाती है और फिर राष्ट्रीय राजनीति में भीन फरत को बढ़ावा मिलता है। जातिगत राजनीतिक बातें राष्ट्र को तब बहुत अधिक नुकसान पहुँचाती हैं जब वो इतिहास को इसी रंग और नफरत के रूप में प्रस्तुत करती हैं। हालांकि ये सच है कि भारत में जातिगत या सामाजिक रूप से भयंकर अत्याचार लोगों पर किए गए हैं लेकिन अगर आज आजाद भारत में उन्हीं बातें को महत्त्व देंगे तो वापिस गुलामी की तरफ बढ़ जाएंगे। राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो लोगों के पास सैद्धांतिक रूप से काफी अधिकार होते हुए भी राजनीतिक क्षेत्र में सीमित विकल्प हैं। राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज देश में एक पार्टी बड़ी–2 सरकारी डकैती डालती है और पूरे देश को महँगाई झेलनी पड़ती है तो दूसरी पार्टी इस विशये को मुद्दा बनाकर सत्ता में आती है और सत्ता में आने के बाद पहले से भी ज्यादा बड़ी लूट करती है हालांकि उसकी आर्थिक लूट तो सत्ता से जाने के बाद ही आँक्ड़ों के रूप में उजागर हो पाएगी लेकिन झूठी बातें और जनता का भावनात्मक शोषण स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

आज राष्ट्र के नाम पर देश का ध्रुवीकरण करना बिल्कुल ठीक है लेकिन नकरात्मक राष्ट्रवाद के द्वारा देश को दो भागों में बाँटना क्या वों ही मानसिकता नहीं है तो देश की आजादी से पहले जिन्नाह द्वारा इस्तेमाल की गई मानी जाती है और जिसके कारण देश का विभाजन हो गया था। आज तथाकथित राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाने वाले लोग राष्ट्र और राष्ट्रवाद का अर्थ तक भी नहीं जानते और हमारे देश की जनता इतना न समझ कि एक बड़ा वर्ग इन तथाकथित राष्ट्रवादियों को साजिश का शिकार हो जाता है वो अपने सबसे बड़े राजनीतिक अधिकार यानि वोट देने के अधिकार को भी इन्हीं साजिशों में फँसकर गलत लोगों को दे बैठते हैं। आज देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पहले से कम नहीं हो रहा बल्कि अलगाववाद पहले से ज्यादा बढ़ रहा है क्या भारत की बहुसंस्कृतवाद की विचारधारा में असहिष्णुता इतनी बढ़ चली है कि अलगाववाद की भावना प्रबल होने लगी है। कई बार तो सरकार को चलाने वाले लोगों की मंशा पर संदेह होता है जब सरकार से जुड़ी पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध बोलने वाले व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही करार दे दिया जाता है। अपने विवेक से सोचने वाला व्यक्ति तब बड़ा दुःखी होता है ज बवह देखता है कि एक ही प्रकार के मुद्दों पर सत्ताधारी पार्टी और मीडिया समान कवरेज दे रही है जबकि उस समय की बड़ी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कई बार तो ऐसा लगता है कि एक विचारधारा के लोग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए खुद ही अपने विरुद्ध दूसरे लोग खड़े करवा देते हैं और फिर दूसरों को राष्ट्रविरोधी धर्मविरोधी का नाम देकर वोटों का अपने पक्ष में एकीकरण करते हैं। कई उदाहरण हमारे पास हैं जहाँ इस प्रकार की मानसिकता दिखाई देती है। मैं

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

एक उदाहरण यहाँ दे रहा हूँ। कुद समय पहले उत्तर प्रदेश में हमलाम नामक एक मुस्लिम युवक को गौ–मास रखने के संदेह में तथाकथित गौ भक्तों द्वारा मार दिया गया जबकि राजस्थान में जयपुर के नजदीक की गऊशाला में इसी दौरान लगभग 4000 गाए मरने के लिए छोड़ दी गई और वो तड़प–2 कर मर गई क्योंकि वहाँ की प्रबंध समिति और गऊ सेवकों ने उन गायों को बरसात के मौसम में एक ही जगह पर बाँध दिया। न तो वहाँ से पानी निकाला गया और न ही गोबर वो सारी जगह दलदल बन गई और गायें बाहर ही नहीं आ पाई और वहीं दम तोड़ दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि ये सब कुछ देखने वाले लोगों की गौ भक्ति कहाँ गई, गायें इतनी कमजोर क्यों थीं, उनके हिस्से का चारा कौन खा रहा था और तथाकथित गऊ भक्तों या राष्ट्रवादियों ने उन गायों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या किया। वैसे राजस्थान में गऊ हत्या के विरुद्ध सख्त कानून है तो फिर सरकार ने क्या किया।

लेकिन बड़ा आ चर्य होता है जब देखते हैं कि 4000 गायों के अप्रत्यक्ष हत्यारों के खिलाफ यहाँ कोई नहीं बोलता क्योंकि वो हिन्दू हैं और तथाकथित गौभक्तों में से ही आते हैं जबकि एक मुस्लमान को संदेह में ही मार दिया जाता है। जब ऐसा इस देश में हो गया तो क्या अलगाववाद की भावना प्रबल नहीं होगी लेकिन आज सच्ची राष्ट्रशक्ति से किसी को कोई मतलन नहीं रहा बस अपनी राजनीतिक वोट बैंक हासिल करने के लिए ब्यान बाजी कर दी जाती है। इस प्रकार के राजनीतिक वातावरण में लोग अपनी स्वतंत्रताओं का उचित फायदा नहीं उठा सकते और वर्तमान ही भविष्य की रूपरेखा तय करता है। आज वर्तमान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संकीर्ण सोच और साम्प्रदायिक भाक्तियों का राजनीतिक प्रभाव बढ़ना हमारे भविष्य की राजनीतिक स्वतंत्रता को हमसे छीन लेगा। पाकिस्तान जैसे देश में शायद उतनी आजादी नहीं है जितनी इंग्लैंड में है क्योंकि कानून का शासन और सम्पूर्ण राष्ट्र के बीच मेल मिलान और सम्पूर्ण राष्ट्र का समान विकास जरूरी है।

अब अगला विषय स्थाई विकास जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो विकास हो रहा है उसे कल के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए बना कर रखना है। आज जो विकास हो रहा है उसे जानने के लिए आज की राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करनी जरूरी है और ये भी जानना जरूरी है कि गुजरे हुए कल में हम क्या थे। हमारी राजनीतिक व्यवस्था और उसके साथ जुड़ी सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था देश की आजादी से पहले क्या थी। हम जानते हैं कि देश की आजादी से पहले जहाँ एक तरफ हम अंग्रेजों के गुलाम थे वहीं दूसरी तरफ सामाजिक रूप से हमारा देश और उसकी जनता इतने भागों में बँटी हुई थी कि उन्हें एक साथ लाना तराजू में मेंढ़कों को इक्ट्ठा करने से कम नहीं था और आर्थिक रूप से तो हमारी स्थिति बेहद दयनीय थी। पूरे दिन एक समय का भोजन मिलना इस देश की बड़ी आबादी का नसीब समझा जाता था। यहाँ तक कि देश की आजादी के बाद भी लगभग बीस वर्शोंतक हम अनाज के लिए दूसरे देशों की तरफ देखते थे। ऐसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में हमारा जो राजनीतिक पर्यावरण था उसने बहुत सी कमियाँ होना स्वाभाविक था लेकिन हमारे देश के अधिकांश नेताओं की जागरूकता और विकास के कारण हम इस स्थिति से बाहर निकलकर आए और आज हमारे देश में अनाज भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। सामाजिक रूप से भी विविधताओं को समझने का मौका मिला है। छूआछुत काफी हद तक समाप्ति की

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

ओर है और राजनीतिक क्षेत्र में काफी बदलाव आ रहे हैं। आज देश में कई पार्टियाँ होने के कारण लोगों के पास विकल्प बढ़े हैं और ये सब हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए शुभ है लेकिन ये सब कुछ अधिक सुधार की तरफ आगे बढ़े और भविष्य में स्थाई रूप से बना रहे ये भी जरूरी है और इसे भविष्य में स्थाई बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम उन मूल्यों को राजनीति में टिकाऊ ढंग से बना कर रखें जो मूल्य देश की आजदी के समय थे। जो भाईचारे, बलिदान, त्याग, प्रेम, स्वतंत्रता, एकता, विकास आदि की भावना स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन और उसके बाद थी वो आज भी बनाकर रखनी जरूरी हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम देश की आजादी के समय साम्प्रदायिक उन्माद और नफरत को नहीं रोक पाए जिसका परिणाम भारत का विभाजन था और अगर आज ये साम्प्रदायिकता या अन्य किसी प्रकार का सामुदायिक उन्माद भारतीय समाज में फैलता है तो एक बार फिर भारत को किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में स्थाई विकास के स्थान पर स्थाई नुकसान की संभावना ज्यादा होगी इसलिए स्थाई विकास के लिए जरूरी है कि हमारे राजनीतिक पर्यावरण में नकरात्मक राजनीति के लिए कोई जगह न हो। आज क मीर के हालात नकरात्मक राजनीति का ही परिणाम है, और इस नकारात्मक राजनीति में जहाँ एक तरफ का मीर के अलगाववादी नेताओं की बड़ी भूमिका है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे नेताओं की समाजपूर्ण मंशा भी इसके लिए जिम्मेदार है और क मीर के हालात धीरे–धीरे पूरे देश की राजनीति में नकारात्मकता फैला सकते हैं। ऐसी बातें हमें समझनी चाहिएं और अपने या अपनी पार्टी के निजी लाभ को राष्ट्रीय लाभ या सम्पूर्ण समाज के हित के आड़े नहीं आने देना चाहिए।

मेरा ये मानना है कि राजनीतिक पर्यावरण में कैसे नकारात्मक और प्रदूषक कारकों को दूर किया जा सकता है। श्रेष्ठ विचारों के माध्यम से क्योंकि कहा जाता है कि कोई युद्ध मैदान में आने से पहले या कोई भी कार्य वास्तविक रूप लेने से पहले कहीं न कहीं विचारों के रूप में मौजूद होता है। अगर विचारों के रूप से ही नकारात्मक विचार को, एवं प्रदूषित विचार को रोक दिया जाए तो वास्तविकता में कोई राजनीतिक प्रदूषण होगा ही नहीं। जैसा कि मैंने शुरु में लिखा था कि विचार आत्मा का पर्यावरण है। इसलिए आत्मा के पर्यावरण को शुद्ध रखना अत्यंत जरूरी है अगर हमारी आत्मा और आत्मा का पर्यावरण शुद्ध होगा तो हमारे विचार और विचारों के कारण राजनीतिक पर्यावरण शुद्ध होगा और शुद्ध राजनीतिक पर्यावरण में राजनीतिक प्रदूषण व नकारात्मकता तथा विशैली राजनीति नहीं होगी। मानवीयता हर तरफ फैली होगी। सभी लोग राजनीतिक मूल्यों को समझोगे और भविष्य में उनको स्थाई रूप से अपने जीवन में लागू रखेंगे तथा आने वाली पीढ़ियों में भी इस प्रकार सकारात्मक राजनीति का संचार होगा और सकारात्मक राजनीतिक ही शुद्ध स्थाई राजनीतिक पर्यावरण प्रदान करेगी।

संदर्भ :

1. जयराम, रमेश, "ग्रीन सिग्नल्सः इकोलॉजी, ग्रोथ एण्ड डेममोक्रेसी इन इंडिया" ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2015
2. कांडपाल, प्रकाश चंद, "एनवायमेंटल पॉलिसी, गवर्नेस एण्ड पॉलिटिक्स : ए साउथ एशियन पर्सपेक्टिव" रुटलेटेज़ इण्डिया (टेलर एण्ड फ्रांसिसी ग्रुप) पब्लिकेशन्स, 2024

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 7.2 ISSN No: 3049-4176

3. सखनन, वेलयुथम, पॉलिटिक्ल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट एण्ड एनवायरमेंट इन मॉडर्न इंडिया" रुटलेज पब्लिकेशन्स, 2023
4. जेफरी डी सेक्स, द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 2015